ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-1* February- 2021
Innovation The Research Concept

भूटान की विकासवादी रणनीति एवं संवैधानिक जागरण

Bhutan's Evolutionary Strategy and Constitutional Awakening

Paper Submission: 11/02/2021, Date of Acceptance: 23/02/2021, Date of Publication: 24/02/2021

महेन्द्र कुमार शर्मा
संविदा व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर,
राजस्थान, भारत

सारांश

विगत कुछ वर्षो से भूटान की प्रशासनिक व्यवस्था में निरन्तर परिवर्तन हो रहे है, मार्च 2005 में भूटान का लिखित संविधान प्रकाशित हुआ ओर उसे भूटान की जनता के सामने रखा गया इन्ही दिनों भूटान नरेश चतुर्थ जिग्मे सिग्ये वांगचुक ने एक सार्वजनिक घोषणा की वे 2008 में लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तर पर आम चुनाव करांयेगे ओर अपने पद से भी मुक्त हो जायेगे सन 2005–06 जनता को नये संविधान की 34 धाराओं को समझने में व्यतीत हुआ भूटान के सभी 20 जिलों में नरेश ने दौरा किया और जनता की आवाज सुनी और समाधान भी किया। भूटान का नवीन संविधान लोकतात्रिक स्तर पर आमचुनाव कराने हेतु तैयार हुआ उल्लेखनीय यह है कि भूटान में राजतंत्रीय व्यवस्था रहते हुए समानान्तर स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने हेतु अपना मानस बनाकर यह सिद्ध करना है कि जो लोकतांत्रिक विकसित देश है उनकी तरह हम भी चलने को तैयार है। दक्षिण एशिया में भूटान द्वारा अपने स्तर को जाहिर करना कि सार्क के देशो में अपना स्थान लोकतांत्रिक चेहरे को प्रयोग में लाकर एक संदेश देना। अपने सबसे पडोसी निकटम भारत देश की लोकतात्रिक पद्धति को भी आदर्श मानकर विविध सन्धिया के माध्यम से वे एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका अदा कर, अपने छोटे देश होने के भाव को व्यापक स्वरूप प्रदान करना है।

Bhutan's administrative system has been continuously changing for the last few years, the written constitution of Bhutan was published in March 2005 and it was placed before the people of Bhutan. The general elections will be held at the level of the system and you will also be freed from your post. In 2005-06, the public spent time in understanding the 34 sections of the new constitution, in all the 20 districts of Bhutan, the King did the deed and heard the voice of the people and also resolved. . The new constitution of Bhutan agreed to hold general elections on a democratic basis; It is noteworthy that while keeping the monarchical system in Bhutan, it is necessary to establish our psyche to establish a democratic system at an equal level, that we should also run like a democratic developed country. is ready. In South Asia, Bhutan expresses its level by giving a message to the SAARC countries by using its democratic face. Taking the role of a good neighbor through a variety of treaties, by considering the democratic system of our closest neighbor India as an ideal, he has to give a broad shape to the feeling of being a small country.

मुख्य शब्दः जी0एन0एच0 (GNH) ड्रकग्यालपों करिछू प्रोजेक्ट, पुनात्सोंग्छू प्रोजेक्ट, संवैधानिक राजतंत्र, शाही भूटान, वांग्चुक,सिचुला संधि, चूखा प्रोजेक्ट, जागरण, डोकलांम विवाद, शोंगडू।

GNH Drakgyalpon Karichhu Project, Punatsongchhu Project, Constitutional Monarchy, Imperial Bhutan, Wangchuk, Sichula Pact, Chukha Project, Jagran, Doklam Dispute, Shongdu.

प्रस्तावना

हिमालय की गोद में वसे इस छोटे से राज्य के नरेश ने अपनी एकाधिकारी सत्ता को समाप्त करने वाला संविधान का प्रारूप स्वीकार कर एक नवीन सन्देश दिया व कीर्तिमान स्थापित किया। 47 वर्षीय सम्राट जिग्मे सिग्ये वांग्चुक द्वारा जो प्रारूप समिति गठित की गई उसके सदस्यों को अत्यन्त जिम्मेदारी का कार्य दिया गया था एवं उन्हें यह संविधान प्रारूप तैयार कर 51 पृष्ठों में सोपना था। यह प्रारूप दस्तावेज प्रजा की मांग किये विना राजा की अधिसता के कम करने की अनूठी की मिशाल था।

राजा का कहना था ''मैं यह प्रारूप आप लोगों से इस उम्मीदों से ग्रहण कर रहा हूँ कि आप मेरी इस आस्था से सहमत है कि संविधान ही देश का भाग्य विधाता होता है।'' उनका कहना था कि राजतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली नहीं है। क्योंकि यह राष्ट्र का भाग्य एक व्यक्ति के हाथ में सौपं देती है। संवैधानिक परिवेश में सकल राष्ट्रीय सुख की अवधारणा एक अनूठी क्रियाविधि है जिसमें प्रत्येक नागरिक को विश्वस्त किया है कि शाही सरकार का मूल भाव प्रत्येक व्यक्ति के सुख की व्यवस्था करवाना है जिसके द्वारा ही राष्ट्रीय विकास को सकल पैमाने पर आकां जा सकेगा। यह अन्य देशों में सचालित जीडीपी का ही दूसरा प्रतिरूप है। भूटान नरेश का संवैधानिक जागरण का भाव था कि पूर्णतया राजतत्रीय व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्रीय व्यवस्था में बदलने की हार्दिक अभिलाषा थी संसद में उनके उदगार यह थे ''समाज की वाध्यता अव यही है कि संसद के सभी सदस्य सकारात्मक विचारों को रखते हुए समझे कि भूटान को एक विस्तार से लिखित संविधान की आवश्यकता है।

शोघ विधि

वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक, पद्धति का प्रयोग अधिकांशतः किया गया है।

प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत प्रतिवेदनों संसदीय कार्यवाहियों का सहारा लिया गया है। द्वितीयक स्रोतों के अन्तर्गत प्रमुख प्रासंगिक पुस्तकों, लेखों, समीक्षाओं, पत्र पत्रिकाओं द्वारा संग्रहीत। राष्ट्रीय पुरातत्व पुस्तकालय (दिल्ली)

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में यह तलाश है कि भूटान की राजतंत्रीय व्यवस्था में संवैधानिक परिवर्तन के आधार पर किस प्रकार धीरे–धीरे प्रशासनिक शैली में विकेन्द्रीकरण की धारा प्रवाहित होती जा रही है तीसरे नरेश जिग्मे दोरजी बांग्चुक की प्रशासनिक पद्धति से लगने लगा है कि राजतंत्रात्मक परिवेश मंथर गति से विकेन्द्रीकरण व लोकतात्रिक पद्धति के हस्तक्षेप की ओर सकारात्मक शैली में अग्रसर हो रहा है। विश्वव्यापी पैमाने पर भूटान जैसे छोटे से देश को उसकी अस्मिता से उपर उठाकर स्वपहचान का परिचय सम्प्रेषित करवाना।

विषय विस्तार

भूटान के विकास व निर्माण की योजनाओं का प्रारम्भिक काल उन प्राथकिताओं से भरा हुआ था। जो उसके अस्तित्व के लिए जरूरी था यानी देश की पॉचवी योजना में (1981–87) प्राथमिकताऐं पूर्णतया बदल गई इस योजना में कृषि तथा औधोगिक क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया। कृषि में विकास करना है तो स्थानीय स्रोतों पर निर्भर रहना होगा तथा स्थानीय नेतृत्व की भूमिका अधिक महत्व रखेगी ,खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भता का निरन्तर प्रयास रहा है।

भूटान के जंगलों पर देश की आर्थिक योजना बहुत ही निर्भर रहती आई है। पॉचवी योजना जो कि छः वर्ष मानी गई थी। जिसकी नीति अधिकांश लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होना तथा विकेन्द्रीकरण की नीति जो गॉवों तक पहूँचानी है भावार्थ है कि भूटान में आर्थिक विकास के दौर को उत्तरोत्तर बढ़ता देखा जा सकता है। देश के मूल्यों की व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है तथा और अधिक बदलाव होने की प्रयास नीति है क्योंकि आर्थिक नीतिपरक विकास ही किसी देश की सांस्कृतिक व मूल्यों को साथ लेकर विकसित होने की इच्छा जाहिर करता है इसलिए शाही भूटान इसका अपवाद नहीं है। यद्यपि भूटान ने अपने देश में मुद्राओं व सिक्कों का चलन 1950 में कर दिया था लेकिन वास्तविक रूप से भूटानी युग का प्रचलन 1960 के वाद से माना जाता है। सर्वाधिक विकास का रूप भूटान में औद्योगिकरण कार्यक्रम के तहत पानी के स्रोतों का सही दिशा में प्रयोग करना जिससे देश को पानी प्रयोग से बिजली प्राप्त होगी वह अर्थव्यवस्था को संतुलित करेगी । 336एम डब्ल्यू का चूखा एच ई प्रोजेक्ट जिसका निर्माण 1974 में हुआ। 60 MW करिछू प्रोजेक्ट, 120 MW का Tala Project, 1095 MW का पुनात्सोंग छू, IHE Project इन बिजली की परियोजनओं में सन 1975 से भारत का स्थापित करवाने में पूर्ण सहयोग रहा है, वहॉ की सड़कों का तथा अस्पतालों का निर्माण कराना आम बात मानी जाती है क्योंकि शाही भूटान का सबसे करीवी पडौसी व्यापार के क्षेत्र में भारत ही माना जाता है तथा परस्पर मैत्री का प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है अभी हाल में ही चीन द्वारा डोकलाम विवाद पैदा किया गया उस समय भूटान सेना ने चीनी सैनिकों से पूरी तरह से सामना करते हुये भारत भूटान मैत्री का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। असल में भूटान प्राचीनकाल से ही एकांतवादी नीति का निर्धारक व पोषक रहा है अपनी संस्कृति व परम्परा की रक्षा करने का दृढ संकल्प कुछ और वर्षो तक चल जाता यदि चीन की तिब्बत में गतिविधिया शुरू नहीं होती । चाहे वह गृहनीति हो या विदेश नीति परिवर्तन तभी होता है जब कोई विशिष्ट परिस्थितिया अस्तित्व के लिये चुनौती बनकर सामने आती है। चीन ने 1959 में तथा 1962 में जो कुछ तिब्बत तथा भारत के साथ व्यवहार दिखाया वह भूटान के लिये अत्यंत भय तथा आंतकित करने वाला था। तथा भूटान को लगा कि अव पुरानी स्थितियों में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है।

भारत का आत्मीय पड़ौसी है भूटान का प्राचीन इतिहास बड़ा ही रोचक पूर्ण है अधिकाशतः यहॉ का लेखाजोखा किसी भी इतिहास की दृष्टि से अनुपलब्ध ही माना जाता है क्योंकि 9 वी शदी में यहॉ बौद्ध धर्म आने के पूर्व का इतिहास अज्ञात ही है। पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति होने से भूटान में उस समय तिब्बत में आन्तरिक अशान्ति होने से बहुत से बौद्धभिक्षु यहॉ आकर रहने लगे थे।

सन 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच प्रसिद्व सिंचुला संधि हुयी, जिसके अन्तर्गत भूटान की सीमावर्ती कुछ भूभाग के वदले कुछ वार्षिक अनुदान देना निश्चित हुआ सन 1907 में ब्रिटिश प्रभाव में राजतंत्र की स्थापना हुई थी। 1949 में भारत भूटान समझोते के तहत भारत ने भूटान की अग्रेजों के समय अधिगृहीत सारी जमीन लौटा दी समझोते के तहत भूटान ने अपनी विदेश नीति तथा रक्षा नीति भारत से सलाह मशविरा करके तय करने का वादा किया था।

कुछ रोचक तथ्य 699 किलोमीटर लम्वी है भारत भूटान की सीमा, 8 अगस्त 1949 में भारत भूटान संधि हुयी। जिसमें भारत ने भूटान की रक्षार्थ प्रतिवद्धता दिखाई, 21 सितम्बर 1971 को भूटान U.N.O का सदस्य बना 18 जुलाई 2008 को भूटान में संवैधानिक लोकतांत्रिक राजतंत्र लागू हुआ 38,394 वर्ग किमी क्षेत्रफल है शाही भूटान का, 7,42,737 जनसंख्या है लगभग भूटान की भूटान की 70 प्रतिशत जमीन वनो से परिपूर्ण है। 94 प्रतिशत लोग कृषि आधृत है। 2004 में भूटान दुनिया का प्रथम तम्बाकू निषेध देश बना था, सन 2000 में ही टी0वी0 इन्टरनेट सेवायें प्रारम्भ हुई।

राष्ट्रीय सुख का अनूठा अभ्युदय

(Gross National Happiness) जी.एन.एच. तथा जी.डी.पी. में अन्तर की दृष्टि से सामूहिक मूल्यात्मक सुख को प्रदान कराना शाही सरकार का मूल ध्येय रहता है। परम्पराओं तथा मूल्यों को आधार मानकर सदभावना का वातावरण तैयार किया जाता है भूटान में इस सम्बन्ध में आयोग भी बनाया गया है जो कि संविधान के नियम कानूनों को विस्तार रूप प्रदान करता है विभिन्न नीतियों को निर्मित करवाना यह आयोग भूटान अध्ययन केन्द्र के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 2008 में पहलीवार सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में भूटान के सम्पूर्ण 20 जौन्खा (जिले) में सही तरीके वहॉ की जनसंख्या आंकड़े लिंगानुपात उम्र तथा व्यवसाय के विविध आंकडों को वहां के नागरिकों के सुख तथा दुख को तुलनात्मक दृष्टि से समय – समय पर विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाने के अन्तर्गत ।

भूटान के चतुर्थ ड्रकग्यालपो जिग्मे सिग्ये वांग्चुक ने इस अवधारणा को मूर्तरूप दिया था, तथा बताया कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण होने से इसे राष्ट्रीय नीति में समाहित किया है। जिसे भूटानी संविधान के अनुच्छेद 09 में वर्णित किया है तथा भूटान के प्रथम चयनित प्रधानमंत्री जिग्मे थिनले द्वारा भी इसे वहुआयामी तरीके से स्थापित करने हेतु प्रयास किये सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी) से, सकल राष्ट्रीय सुख (जी.एन.एच.) अधिक प्रभावी तथा महत्वपूर्ण है।

जी.एन.एच. कमीशन 2008 अनुच्छेद–9 के तहत भूटान में स्थापित किया गया है जिसमें मूलरूप से जी.एन.एच के राष्ट्रीय स्तर पर शाही भूटान के समग्र विकास हेतु 9 प्रकार के आयाम निर्धारित किये गये है।

1. मानसिक रूप से स्वस्थ
2. समय का सही उपयोग
3. सामुदायिक जीवन्तता
4. सांस्कृतिक विविधता
5. पारिस्थतिकी
6. जीवन स्तर
7. स्वास्थ्य
8. शिक्षा
9. सुशासन

इन सभी आयामों के संयोजन तथा परस्पर निर्भरता के परिणामतः भूटान का सकल राष्ट्रीय सुख अपना स्वरूप व क्षेत्र निर्धारित करता है।

His Majesty King Said

"GNH Has Come to Means So Maney Things to So Maney People But to Meit Signifies Simply, Development With Value".जी.एन.एच की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में शाही नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल ने जो भावना प्रदर्शित की है उसमें सामान्य तरीके से विकास के साथ आधारभूत मूल्य दयालुता, समानता, और मानवता, आदि तत्वों को एकीकृत करना तथा आर्थिक वृद्धि के लिये उत्साहित करना आदि है। भूटान के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु ऐसे निर्णय लेना जो राष्ट्रीय चेतना तथा जीएनएच के दर्शन को विकसित कर सके। साधारणतया जीएनएच दर्शन द्वारा यह स्थापित करने का प्रयास है जिसमें अत्यावश्यक रूप से विकास की दृष्टि को उच्च स्तर पर रखना तथा शाही सरकार की यह निश्चित रूप से जिम्मेदारी है कि ऐसी स्थिति पैदा करना जिसके अन्तर्गत अधिकतम सुख को प्रत्येक भूटानी नागरिक तक पहुंचाना है। लोकनीति के अन्तर्गत जीएनएच का ऐसा ढांचा तैयार करना है जिसका आधार मूलरूप से चार खम्भों पर आधृत है।

1. समानता पर आधारित सम्माजिक आर्थिक तथा संपोषणीय विकास
2. शाही भूटान के पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना
3. भूटानी संस्कृति का उन्नयन तथा संरक्षित करना
4. शाही भूटान में एक अच्छे वातावरण युक्त सुशासन का अस्तित्व

वर्तमान भूटान में संविधान द्वारा यह उपवधित किया गया था तथा प्रस्तावना में यह अनुशंसा की गई कि भूटान के नागरिकों को उनकी एकता समानता तथा अच्छे जीवन निर्माण हेतु आदेशित किया गया है।

अनुच्छेद 9.2 कहता है "The state shell strive to promate those condition that will enahle the pursuit of GNH" भूटान के विकास के प्रयासों मे इन चार पैमानों का विशेष योगदान रहा है। तथा जीएनएच की बढोतरी ही महत्वपूर्ण इसीलिये है कि भूटान के राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में 11 वी पंचवर्षीय योजना की आधारभूत विकासवादी नीति रही है। इन्हीं स्तभों पर टिकी है इस नीति का महत्व इसलिये भी है। संस्थाओं का प्रभावशाली महत्व जीएनएच के ढांचे को मजवूती प्रदान करती है एवं जीएनएच आयोग द्वारा एक नोडल अभिकरण के रूप में नीति के निर्धारण तथा उसके क्रियान्वयन तथा योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण कार्य निष्पादन करना है जीएनएच की उपयोगिता से ही शाही भूटान में एक सफल आर्थिक रूप से विकसित स्तर बनाना तथा परिणामतः लोकतंत्र की स्थापना द्वारा आधारभूत जीएनएच की सार्थकता सिद्ध करता है।

भूटान में सवैधानिक जागरण

सन 1907 में भूटान अपने अस्तित्व में आया था अर्थात स्वतंत्रता का परिवेश देखा था 21 वीं शदी में भूटान के 100 वर्ष दिसम्वर 2008 में पूर्ण हुये, तथा पहले चुनाव को भूटान ने स्वीकार किया था। 8 मई 2008 को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुयी भूटानी संसद का सत्र आहूत किया गया। 47 सदस्यी राष्ट्रीय असेम्वली के तथा 25 सदस्य राष्ट्रीय कांउसिल के थे ड्राफ्टिंग कमेटी पूर्णत सोसाइटीज के प्रतिनिधियों पर आधृत थी। भूटान की

वर्तमान व्यवस्था लोकतांत्रिक संविधानवादी राजतंत्र (Constitutional Democratic Monarchy)की चल रही है ध्यातव्य है कि शाही भूटान के चतुर्थ ड्रकग्यालपों जिग्मे सिग्ये वांगचुक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब भूटान को लिखित संविधान स्वीकार करना ही होगा। क्योंकि वे जनता के साथ इतने घुलमिल गये थे कि उनके साथ पंगत में बैठकर भोजन करना तथा उनके दुख दर्द के साथ बैठकर दूर करना आदि एवं संविधान निर्माण की बात रख दी भूटान में लोकतंत्र की स्थापना सुधारवादी मानी गई 18 जुलाई 2008 को शाही भूटान ने संविधान को अधिनियमित कर स्वीकार किया जिसमें 35 अनुच्छेद तथा 04 अनुसूचियां है। संविधान प्रारूप निर्माण सन 2005 में ही हो गया था इसका मूल उद्देश्य राजतंत्र में संवैधानिक लोकतंत्र लाना था।

ड्रक नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष Rong Thong Kunley Dorji द्वारा प्रस्ताव के सुझाव रखे थे तथा भूटान संसद का 80 वां अधिवेशन संविधान परिवर्तन का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। संवैधानिक पदों का विवरण इस प्रकार है।

1. भूटान का मुख्य न्यायाधीश तथा 4 ड्रेगन
2. उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश तथा 8 ड्रेगन
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त
4. आडिटर जनरल
5. लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष
6. भृष्टाचार निरोधक आयोग का अध्यक्ष

निष्कर्ष

उन्नत लामाओं (ELEVATED LAMAS) की धरती व पर्वतराज हिमालय की तलहटी में वसा हुआ विकसित राष्टों की तुलना में शैशवस्था से आगे की ओर जाने के लिये उधत शाही भूटान (Royal Bhutan) विश्व में अपनी अनूठी पहचान व मिशाल रखता है यहॉ की रमणीय घाटियां सीमित क्षेत्र में व्यतीत जीवन शैली भोगोलिक दृष्टि में दक्षिण एशियायी देशों के साथ भारत व चीन के मध्य अपना स्वाभिमान के साथ अस्तित्व बनाये हुये है। यहॉ की बदलाव नीति एक विकासवादी लोकतात्रिक मॉडल का स्वरूप प्रस्तुत कर रही है, राजंतत्रीय व्यवस्था का या राजशाही का नरेश द्वारा परित्याग करना सारी शक्तियॉ संविधान को सोंप देना ये हालांकि शाही राजा अस्तित्व में तो रहेगा लेकिन अधिसत्ता को हस्तान्तरित करके संवैधानिक नरेश बनाने का बहुत बडा परिवर्तनीय कदम रहा है। इसमें केविनेट सोग्डू के प्रति जवावदेही होगी, देश की एकता, सम्प्रभुता, सुरक्षा का दायित्व नरेश पर ही रहेगा। वयस्क मताधिकार का लागू किया जाना द्विसदनीय संसद उपरी सदन में मनोनीत सदस्यों का होना तय किया गया।

नरेश द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) की जगह सकल राष्ट्रीय सुख (जीएनएच) को विकास का मापदण्ड माना गया और उसे वर्तमान में सकारात्मक तरीके से संचालित भी किया जा रहा है। इसके माध्यम एक पासरदर्शी सुशासन निष्पादित कर विकास के नये आयाम, प्रतिमान, मॉडल स्थापित कर लोकतात्रिक पद्धति जो कि विश्वमान्य है उसे संपोषणीय दायरे में लाकर संर्वागीण विकास करना प्रमुखतम है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Mishra, R.C. 1977: Recent trends in bhutaniese politics in south "Asian studies vol.XII, No 1-2, P.132-44*
2. *Mishra, R.C 1980: Bhutan china relation in "china report", Vol. XVII No.2,PP-43-50. Delhi.*
3. *Mishra R.C., 1982: Tibetans in Bhutan: problem of repartiation in china report,Vol XVII, No 5, P25-32*
4. *कपिलेश्वर लाभः इण्डिया एण्ड भूटान सिन्धु पब्लिकेशन.*
5. *नारी स्तमजी Enchanted frontiers*
6. *ध्रुव रिजाल Administrative system in Bhutan.*
7. *राम–राहुलः मॉडर्न भूटान, रोयल भूटान– / political History*
8. *इण्डिया टुडे दिसम्बर 2002– सुमित मित्र (थिंपू में)*